इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 11 जून, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 5
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 6
विनियामकों के कथन ----------6
आर्थिक संवेष्टन ----------7
नयी नियुक्तियाँ ---------- 8
विदेशी मुद्रा ---------- 8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 2री द्विमासिक बैठक 2021-22 : मुख्य विशेषताएँ

मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2021-22 की दूसरी द्विमासिक बैठक 2 से 4 जून, 2021 तक आयोजित हुई। उक्त बैठक की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर क्रमश: 4% और 3.35% पर अपरिवर्तित रहीं।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दरें 4.25% पर ही बरकरार रहीं।
- 10.5% के पूर्ववर्ती अनुमान के स्थान पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अब 9.5% रहने की आशा है।
- वित्त वर्ष 2021-22 की 2री तिमाही के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपए का सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) लागू किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के 5.1% रहने का अनुमान है।

भारतीय रिजर्व बैंक की चलनिधि सुविधा के कारण होटलों, पर्यटन क्षेत्र को मिला बढ़ावा

विद्यमान वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने होटलों और रेस्तराओं, ट्रैवेल एजेंसियों, पर्यटन प्रचालकों तथा साहसिक कार्य/विरासत (adventure/heritage

) सुविधाओं, विमानन की अनुषंगी सेवाओं, ग्राउंड हैंडलिंग एवं आपूर्ति शृंखला जैसे संपर्क-प्रधान क्षेत्रों और और निजी बस प्रचालकों, कार मरम्मत सेवाओं, समारोह/सम्मेलन आयोजकों, स्पा क्लीनिकों आदि जैसी अन्य सेवाओं को समर्थ बनाया है। 31 मार्च, 2022 तक पुनर्खरीद (repo) दर पर तीन वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की एक अलग चलनिधि सुविधा की घोषणा की गई है।

कोविड से संबन्धित चुनौतियों से निपटने के लिए सिडबी को विशेष चलनिधि सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को आगे उधार देने और पुनर्वित्तीयन के उद्देश्यों के लिए 16,000 करोड़ रुपए की एक विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करेगा। यह उपाय सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) के समक्ष वैश्विक महामारी से उपस्थित होना वाली चुनौतियों को न्यूनीकृत करने हेतु किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का दर्जा दे कर कोविड संकट से निपटने में उनकी सहायता की

कोविड संकट के बीच सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के समक्ष उपस्थित हो रहे चलनिधि से जुड़े मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (SFBs) द्वारा (500 करोड़ रुपए के आस्ति आकार वाली) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को व्यक्तियों को आगे उधार देने हेतु दिये गए ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध कराई गई इस सुविधा के तहत संवितरित ऋणों को चुकौती की तिथि अथवा परिपक्वता, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा। 31 मार्च, 2021 के दिन बैंक के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के 10% तक के बैंक ऋण की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य-रक्षा क्षेत्र को आगे उधार देने हेतु बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए की सदा-सुलभ चलनिधि सुविधा

कोविड-19 की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने आकस्मिक स्वास्थ्य-रक्षा को आगे उधार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक विशेष सदा-सुलभ चलनिधि की घोषणा की है। यह विशेष प्रावधान 4% की पुनर्खरीद (repo) दर पर तीन वर्ष तक के लिए किया गया है जो 2019-20 के निजी अंतिम उपभोग व्यय (6 लाख करोड़ रुपए) के तहत भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 9% होता है। जिन बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से निधियाँ प्राप्त कर रखी हैं उन्हें कोविड से संबन्धित स्वास्थ्य-रक्षा की मूलभूत सुविधा और सेवा क्षेत्र में परिचालन करने वाले हितधारकों को निधियाँ प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नयी उधार सहायता प्रदान करनी होगी। उक्त योजना 7 मई, 2021 से 31 मार्च 2022 तक परिचालन में रहेगी।

लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए 10,000 करोड़ रुपए के तीन वर्षीय विशेष दीर्घावधि पुनर्खरीद परिचालन

भारतीय रिजर्व बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और असंगठित क्षेत्र की ऐसी अन्य कंपनियों, जो कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित हुई हैं, को उचित सहायता प्रदान करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए का एक तीन वर्षीय विशेष दीर्घावधि पुनर्खरीद परिचालन (SLTRO) करेगा। यह उपाय प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के नए उधार अभिनियोजित करने में समर्थ बनाएगा। यह सुविधा 31 अक्तूबर, 2021 तक उपलब्ध होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का लाभांश अंतरित करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक की लेखांकन अवधि में (पूर्ववर्ती जून-जुलाई से) अप्रैल-मार्च वाले परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 589वीं बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष रकम 31 मार्च को समाप्त नौ महीनों की अवधि (जुलाई, 2020 - मार्च, 2021) के लिए केंद्रीय सरकार को अंतरित कर दी जाएगी। यह अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक की किफ़ायती पूंजी से संबन्धित नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाएगा। उक्त समिति की सिफ़ारिश के अनुसरण में शीर्ष बैंक ने अपने तुलनपत्र के 5.5% का न्यूनतम आकस्मिक जोखिम भंडार भी बनाए रखा है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर उपायों का एक सेट लागू किया

बैंकिंग सुविधा से वंचित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बैंकिंग प्रणाली में समावेश को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को उनकी निवल एवं सावधि देयताओं (NDTL) से संवितरित ऋण को आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना के लिए घटाने/व्यवकलित करने की अनुमति प्रदान की थी। वर्तमान में 25 लाख रुपए तक के एक्सपोजर के लिए तथा 1 अक्तूबर, 2021 को समाप्त पखवाड़े तक संवितरित ऋण के लिए उपलब्ध होने वाली यह सुविधा अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2021 के दिन जिन व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा जिनका कुल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपए तक था और जिन्होंने कोई पूर्ववर्ती पुनरसंरचना ढांचा नहीं अपनाया है, उन्हें कोविड से संबन्धित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान ढांचे 2.0 के अधीन पात्र माना जाएगा।

अपने ग्राहक को जानिए अद्यतनकरण 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि जहां अपने ग्राहक को जानिए का आवधिक अद्यतनकरण अपेक्षित/ अनिर्णीत हो, वहाँ बैंकों को ग्राहक के खातों के समक्ष दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोविड की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में कई ग्राहकों को उनके अपने ग्राहक को जानिए को अद्यतन करने में जो कठिनाई हो रही है उसे ध्यान में रखते हुये शीर्ष बैंक ने उक्त प्रक्रिया को पूरा करने हेतु ऐसे ग्राहकों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का समय दिया है जिनके बैंक अपने ग्राहक को जानिए अद्यतनकरण के लिए कोई डिजिटल विधि उपलब्ध नहीं कराते तथा जिनके लिए गैर-अद्यतनकरण का अभिप्राय होगा उनके बैंक खातों पर रोक लग जाना।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

1 अगस्त से राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह (NACH) सुविधा प्रति दिन उपलब्ध होगी : भारतीय रिजर्व बैंक

राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह (NACH) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा परिचालित एक थोक भुगतान प्रणाली है। यह काफी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को वेतन, पेंशन, ब्याज, लाभांश तथा अन्य भुगतानों एवं निवेशों के भुगतानों और उसके साथ ही बिजली, गैस, जल आदि जैसे भुगतानों के संग्रहण को सुगम बनाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह सुविधा उन्हीं दिनों उपलब्ध होती है जब बैंक कार्यरत होते हैं। 1 अगस्त, 2021 से राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उपायों की शुरूआत की

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच चलनिधि सहायता उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने आर्थिक स्थिति को प्रचंड रूप से परिवर्तित कर दिया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये उभरती स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य जारी रखेगा। भारत ने मुद्रास्फीति वक्र को समतल बना दिया है, किन्तु स्थिति बदल गई है। उन्होंने सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम 1.0 के तहत 50,000 करोड़ रुपए की सदा-सुलभ सुविधा के अधीन तीन वर्ष की अवधि के साथ पुनर्खरीद दर पर 35,000 करोड़ रुपए की दूसरी खरीद की घोषणा की, जो 31 मार्च, 2022 तक खुली रहेगी। प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के उपयोग हेतु लघु वित्त बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक के लक्ष्यंकित दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालन किया जाएगा।

आर्थिक संवेष्टन

कृषि, मझोले उद्योगों को ऋण में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति, खाद्येतर ऋण वृद्धि घटकर 4.9% हुई

बैंक ऋण के सेक्टर-वार अभिनियोजन पर मार्च, 2021 की अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जहां कोविड से प्रभावित बैंकों में खाद्येतर ऋण वृद्धि में 4.9 की कई दशकों पहले जितनी गिरावट आई, वहीं कृषि क्षेत्र और सम्बद्ध गतिविधियों को ऋण वृद्धि में मार्च, 2020 के मुक़ाबले मार्च, 2021 में 12.3% की बढ़ोतरी हुई तथा मझोले उद्योगों को ऋण में एक वर्ष पहले के 0.7% के संकुचन की तुलना में मार्च, 20021 में 28.8% की तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई।

निर्यात में 197% की वृद्धि दर्ज हुई, आयात 166% बढ़ा

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2021 के लिए जारी प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार भारत का माल निर्यात 197.03% बढ़कर 30.21 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथा माल का आयात 165.99% बढ़कर 45.45 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिससे व्यापार घाटा उस माह के दौरान बढ़कर 15.24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुये घाटे से 120.34% अधिक रहा।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति बढकर 10.49% हुआ, जो 11 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गया

अप्रैल में भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति (WPI) 10.49 % रहकर 11 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुँच गई। यह मुख्यत: ईंधन एवं जिंस मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण हुआ जिसके फलस्वरूप स्फीतिकारी दबावों का जमावड़ा परिलक्षित हुआ। ऐसा आधारभूत प्रभाव के कारण भी हुआ।

अप्रैल में माल और सेवा कर (GST) की वसूली 1 ट्रिलयन का स्तर पार कर गई

मार्च, 2021 में पिछले उच्च रिकार्ड को तोड़ते हुये माल एवं सेवा कर की वसूली ने 1.41 ट्रिलियन रुपए रहकर अप्रैल, 21 में एक नया रिकार्ड कायम किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में माल और सेवा कर राजस्व पिछले माह की वसूलियों की तुलना में लगभग 14% अधिक रहे।

अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.29% रही, मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 22.4% हो गया

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापे जाने पर देश की खुदरा मुद्रास्फीति ख्द्य मूल्यों में कमी के कारण अप्रैल माह में घटकर 4.29% आरएच गई। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ओद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जरिये मापे जाने पर भारत के कारख़ाना उत्पादन में मार्च में वर्षानुवर्ष 143.4 के आधार पर 22.4% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

नयी नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम	**संस्था का नाम**
श्री जोस जे॰ कत्तूर	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 मई, 2021 के दिन बिलियन रुपए	28 मई, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4333464	598165
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4010076	553529
(ख) सोना	276061	38106
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10975	1515
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	36352	5016

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मई, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.16400	0.24300	0.44700	0.66800	0.88200
जीबीपी	0.13400	0.3168	0.4439	0.5858	0.6925
यूरो	-0.50000	-0.460	-0.390	-0.320	**-0.240**
जापानी येन	-0.03380	-0.011	0.004	0.006	0.023
कनाडाई डालर	0.59000	0.70000	0.978	1.216	1.400
आस्ट्रेलियाई डालर	0.11800	0.210	0.400	0.680	0.920
स्विस फ्रैंक	-0.66500	-0.633	-0.558	-0.473	-0.388
डैनिश क्रोन	-0.11460	-0.1030	-0.0530	-0.0105	0.0815
न्यूज़ीलैंड डालर	0.39300	0.600	0.875	1.123	1.335
स्वीडिश क्रोन	-0.02000	0.056	0.156	0.271	0.397
सिंगापुर डालर	0.31500	0.405	0.600	**0.810**	0.973
हांगकांग डालर	0.22000	0.275	0.450	0.660	0.855
म्यामार	2.00000	2.150	2.350	2.550	2.680

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम (G_SAP)

सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम चलनिधि प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ किया गया एक अतिरिक्त साधन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारम्भिक प्रतिबद्धता के साथ एक सुस्पष्ट स्वरूप वाले संरचित खुले बाजार के परिचालन (OMO) की ऐसी प्रतिबद्धता है जो बाजार के रुख की परवाह किए बिना सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करने से संबन्धित होती है। यह कार्यक्रम खुले बाजार के परिचालन, चलनिधि
समायोजन सुविधा (LAF), टिल्ट्रो (TILTRO) आदि जैसे अन्य चलनिधि प्रबंधन

परिचालनों को बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

डेल्टा

डेल्टा वह अनुपात है जो किसी आस्ति, सामान्यतया किसी विक्रेय प्रतिभूति के मूल्य में परिवर्तन की उसकी व्युत्पन्नी (derivative) के मूल्य में परिवर्तन से तुलना करता है। डेल्टा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है जो क्रय विकल्प के मामले में 0 और 1 के रूप में धनात्मक तथा विक्रय विकल्प में 1 और 0 के रूप में ऋणात्मक होगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित लेखांकन और लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	14 से 16 जून, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	18 से 20 जून, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र अध्ययन और अनुपात विश्लेषण	18 से 19 जून, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
ऋण मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (कारपोरेट ऋण पर बल)	21 से 23 जून, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	24 से 26 जून, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाओं का स्थगन

मई 2021 माह में निर्धारित जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं और उनके कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करते हुये जून, 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षाओं की संशोधित तिथि बाद में घोषित की जाएगी तथा वह वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए पुन: पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि के लिए उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छ: चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2021 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) की एक संयुक्त पहलकदमी है। इसका उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी व्यवहार्य शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना है जिनमें उद्योग को उल्लेखनीय रूप से योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 मई, 2021 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। परीक्षाएँ दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को आयोजित की जाती हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश एवं इस विधि की परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के
लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam_related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों

एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट" के अप्रैल- जून, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
"इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग - न्यू नार्मल"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के

लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

110
100
90
80 शृंखला 1

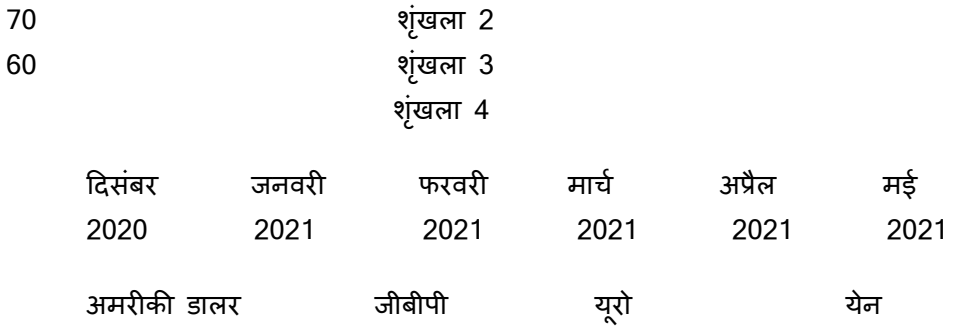

स्रोत : एफबीआईएल

समग्र जमा वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

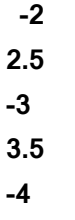

4.5
-5

नवंबर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

7
6.5
6
5.5
5

नवम्बर 2020	दिसम्बर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021

भारित औसत मांग दरें

3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3

दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021	अप्रैल 2021	मई 2021

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

53,000.00
52,000.00
51,000.00
50,000.00
49,000.00
48,000.00
47,000.00
46,000.00
45,000.00

दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
2020	2021	2021	2021	2021	2021

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7.00
6.5
6
5.5
5

अक्तूबर	नवम्बर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2020	2020	2020	2021	2021	2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

6
5
4
3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन जून, 2021